

## राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

### प्रलिमिस के लिये:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline - NMP), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust - InvIT), ग्लोबल वार्स्मगि, महामारी, स्थानकी गरीबी।

### मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, वभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप एवं उसके नियमण तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

## स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अवसंरचना में नए नियम के लिये संसाधन उत्पन्न करने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline - NMP)** के तहत एक परसिंपत्रा पुनर्चक्रण अभियान चलाने का नियमण लिया है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र के परसिंपत्रा पुनर्चक्रण अभियान से लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2021-22 में लगभग 0.97 ट्रिलियन रुपए और वर्ष 2022-23 में 1.32 ट्रिलियन रुपए के मुद्रीकरण मूलयों के साथ लेनदेन पूरा किया गया।

### राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है?

- परचियः**
  - राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) में सड़कों, रेलवे, बजिली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उद्योग जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परकिलिपना करता है।
  - NMP के माध्यम से मुद्रीकरण में गैर-प्रमुख संपत्तियों के विनियोग के माध्यम से मुद्रीकरण को छोड़कर केवल मुख्य संपत्तियों शामिल हैं। वर्तमान में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और CPSE की संपत्ति को शामिल किया गया है।
  - NMP की पहुँच को व्यापक बनाने और अंततः संघीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर संपत्तियों को शामिल करने के लिये सरकार वर्तमान में राज्यों से संपत्ति पाइपलाइनों का आयोजन एवं संकलन कर रही है।
    - प्रक्रया को सुव्यवस्थित करने के लिये, भूमि अचल संपत्ति और अवसंरचना सहित गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत **नियश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management - DIPAM)** से **सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises - DPE)** में स्थानान्तरित किया जा रहा है।
  - इस पाइपलाइन का उद्देश्य **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline - NIP)** के तहत वित्त वर्ष 2015 तक छह वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के नियमण का समर्थन करना है।
    - NMP के लिये समय-सीमा को रणनीतिक रूप से **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** के तहत शेष अवधि के साथ समाप्त करने के लिये नियंत्रित किया गया है।

#### NMP की आवश्यकता:

- लागत में वृद्धि:** कुछ मामलों में, परियोजना का कार्य पूरा होने में अधिक समय लग जाता है, जिससे परियोजना की लागत इतनी बढ़ जाती है कि यह परियोजना शुरू होने के समय ही अव्यवहार्य हो जाती है।
- ओवरकैप्टिलाइजेशन:** अधिकांश सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपात शायद ही कभी देखा जाता है, जिससे उनका ओवरकैप्टिलाइजेशन होता है।
- संसाधनों का अनुकूलन:** लागत में वृद्धि और परियोजना में देरी आंशका रूप से अकुशल संसाधन आवंटन तथा उपयोग के कारण होती

है।

- NMP का लक्ष्य नजी क्षेत्र की दक्षता और बाज़ार-संचालित दृष्टिकोण पेश करके संसाधनों का अनुकूलन करना है, जिससे इनपुट तथा आउटपुट का बेहतर संरेखण सुनिश्चित हो सके।
  - समन्वय चुनौतियाँ: अंतर-मंत्रालयी तथा अंतर-विभागीय समन्वय की कमी से परियोजना निषिपादन में अक्षमताएँ एवं देरी का सामना करना पड़ सकता है।
    - NMP सार्वजनिक तथा नजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है जिससे अवसंरचना के विकास के लिये अधिक समन्वय एवं सुव्यवस्थिति दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
  - शर्म सुधार तथा नरिण्य लेना: शर्म सुधारों को कार्यान्वयिता करने में देरी, अनुचित नरिण्य लेने तथा अपरभावी शासन से सार्वजनिक अवसंरचना की परसिंपत्तयों परभावति होती है।
- **NMP का महत्व:**
- अरथव्यवस्था की बेहतरी: यह एक वशिष्ठ पहल है जिससे अरथव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, बेहतर रोज़गार के अवसर सृजति होंगे एवं भारतीय अरथव्यवस्था की प्रतिसिपरदधारतमकता बढ़ेगी।
    - NMP प्रधानमंत्री गतिशक्ति से संबद्ध है जो भारत में अवसंरचना के विकास के लिये एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। गति शक्ति एक व्यापक तथा सुदृढ़ अवसंरचना नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है जबकि NMP का लक्ष्य नई परियोजनाओं को वित्तीयोपयोग करने के लिये मौजूदा अवसंरचना की परसिंपत्तयों का मुद्रीकरण करना है।
    - एक पहल की सफलता अन्य पहल के लक्ष्यों को सुदृढ़ तथा प्राप्त करने में सहायता कर सकती है जो भारत की समग्र आरथिक वृद्धि एवं विकास के योगदान कर सकती है।
  - कम उपयोग वाली सार्वजनिक परसिंपत्तयों का उपयोग: NMP गैर-रणनीतिक निमिन प्रदर्शन करने वाली सरकारी स्वामतिव वाली परसिंपत्तयों से निश्चय पूँजी का उपयोग करने का समर्थन करता है।
    - यह इस प्रकार प्राप्त धन को नई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पुनर्नविश करने और ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसी परसिंपत्तयों के संवरद्धन की भी प्रक्रिया करता है।

■ **उपलब्धियाँ एवं अपेक्षाएँ:**

- खनन क्षेत्र: वर्ष 2023-24 में परसिंपत्तयों के मुद्रीकरण का केंद्र खनन क्षेत्र, वशिष्ठ रूप से कोयला ब्लॉक तथा अन्य खदानें रही हैं।
  - वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र में उपलब्धिलागभग 55,000-60,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो कि **8,726** करोड़ रुपए के प्रारंभिक लक्ष्य से अधिक है।
  - वित्त वर्ष 2023 का लक्ष्य 6,060 करोड़ रुपए से बढ़कर 37,500 करोड़ रुपए हो गया जिसमें लगभग 68,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई।
  - खनन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022 में 3,394 करोड़ रुपए की तुलना में लक्ष्य से अधिक, 68,000 करोड़ रुपए अर्जति किया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): बाराउनफील्ड परसिंपत्ति पुनरचक्रण (Brownfield Asset Recycling) में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में NHAI को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है।
  - यह उपलब्धिटोल ऑपरेट ट्रांसफर (ToT), प्रतिभूतिकरण तथा **इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT)** मॉडल के मिश्रण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- वित्त वर्ष 2024 में अन्य क्षेत्रों हेतु अपेक्षाएँ:
  - ऊर्जा उत्पादन तथा पारेषण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में **15,300** करोड़ रुपए के अपने संयुक्त लक्ष्य को पूरा किया जिसके वित्त वर्ष 2024 में 26,700 करोड़ रुपए के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले लगभग 20,000 करोड़ रुपए की उपलब्धिके साथ अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है।
  - रेलवे, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 के लिये 44,907 करोड़ रुपए से घटाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, वित्त वर्ष 2023 में 8,000 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 8,000-10,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने की संभावना है।
    - हालाँकि रेलवे ने स्टेशनों जैसी प्रस्तुति परसिंपत्तयों के मुद्रीकरण में अत्यधिक प्रगति नहीं की है किंतु यहलेलवे कॉलोनी पुनर्विकास, गति शक्ति (Gati Shakti) माल दुलाई ट्रमनिलों एवं रोलिंग स्टॉक संबंधी संव्यवहार की पूरतिकरण।
  - तेल और गैस क्षेत्र ने लगभग **4,000** करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है तथा मार्च 2024 तक यह 8,000 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

## NMP से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- करदाताओं के धन जारी करना: करदाताओं ने सार्वजनिक संपत्तयों पर संभावति दोहरे शुल्क के बारे में चति व्यक्त की है। इन परसिंपत्तयों के निर्माण के लिये वित्तीयोपयोग के बाद, अब उन्हें नजी संस्थाओं को उनके मुद्रीकरण के बाद भुगतान के माध्यम से उनका उपयोग करने हेतु अतरिकित लागत का सामना करना पड़ता है।
  - चुनौती आरोपों के इस कथति दोहराव से निपटने और इन परसिंपत्तयों के प्रबंधन तथा उपयोग में सार्वजनिक नविश एवं नजी भागीदारी के बीच उचति संतुलन सुनिश्चित करने में नहिति है।
- संपत्ति और मुद्रीकरण का चक्र: NMP द्वारा नई संपत्ति सिरजति होने तथा बाद में सरकार के लिये देनदारी हेतु उसका मुद्रीकरण करने संबंधी एक दुष्चक्र निर्मिति होने की काफी संभावना है।
- संपत्ति-विशिष्ट चुनौतियाँ: इसमें गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निमिन स्तर, बजिली क्षेत्र की परसिंपत्तयों में वनियमति टैरफि, चार लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों में नविशकों के बीच कम उच्चतिथा इकाई हस्सेदारी रखने वाले कई हतिधारक शामिल हैं।
- एकाधिकार: NMP की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि हस्तांतरण से एकाधिकार उत्पन्न होगा, जिससे कीमत में वृद्धि होगी।
  - स्वामतिव के सुदृढ़ीकरण से वशिष्ठ रूप से राजमार्गों और रेलवे लाइनों के मामले में एकाधिकार हो सकता है। यह चति कम प्रतिसिपरदधा और बाजार की गतिशीलता की संभावना पर केंद्रित है, जिसके परणिमस्वरूप संभावति रूप से अंतमि उपयोगकरताओं के लिये उच्च लागत हो सकती है।

## आगे की राह

- नविशकों, सरकारी एजेंसियों और जनता सहति हतिधारकों के बीच वशिवास बनाने के लिये परसिंप्टटमुद्रीकरण प्रक्रया में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आरथिक विकास, रोज़गार सृजन और बेहतर बुनियादी ढाँचे के संदरभ में परसिंप्टटमुद्रीकरण के लाभों के बारे में बताइये।
- उभरती चुनौतियों और अवसरों से नपिटने के लिये नीतिढाँचे को लगातार परष्कृत तथा अद्यतन करना अनिवार्य है।
- एक सहायक वनियामक वातावरण सुनिश्चिति करें जो नजीि कषेत्र की भागीदारी और नविश को प्रोत्साहित करें।
- परसिंप्टटमुद्रीकरण परियोजनाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिये एक मज़बूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करें।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?:

प्रश्न1. श्रम प्रधान नरियातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में वनिरिमाण क्षेत्रक की वफिलता का कारण बताइए। पूंजी-प्रधान नरियातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान नरियातों के लिये उपायों को सुझाइए। (2017)

प्रश्न2. हाल के समय में भारत में आरथिक संवृद्धिकी प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धिके तौर पर कथिा जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तरक प्रस्तुत कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/24-01-2024/print>

